श्री राम नरेश यादव

राज्यपाल, मध्यप्रदेश

का

अभिभाषण

मध्यप्रदेश विधान सभा अधिवेशन

19 पौष, 1935 शक भोपाल, गुरुवार, 9 जनवरी 2014

माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यगण,

01. चौदहवीं विधानसभा के इस प्रथम सत्र में आप सब का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन है। मध्यप्रदेश में विधानसभा निर्वाचन का लोकतांत्रिक महापर्व शांतिपूर्वक सम्पन्न हुआ है। इसके लिये सभी प्रदेशवासी, राजनीतिक दल, शासन-प्रशासन बधाई के पात्र हैं। चुनाव-दर-चुनाव मतदान का प्रतिशत बढ़ना इस बात का संकेत है कि हम इस संबंध में जागरूकता बढ़ाने में सफल हो रहे हैं।

02. मध्यप्रदेश में मेरी सरकार तीसरी बार भारी सकारात्मक जनादेश के साथ लौटी है। प्रदेश के इतिहास में यह अपने किस्म की अनूठी घटना है। स्पष्ट है कि जनता का यह अभूतपूर्व विश्वास तभी हासिल होता है जब घोषणाएं धरातल पर मूर्त रूप लेती हैं, जब शासन की योजनाएं वास्तव

में जनता को लाभ पहुंचाती हैं। मेरी सरकार अपनी जनोन्मुखी नीतियों और कार्यक्रमों के कारण स्वयं को व्यापक जनस्वीकृति के योग्य सिद्ध कर सकी है।

03. मेरी सरकार तेज गति के साथ काम करने के संकल्प बोध और समर्पण भावना की सरकार है। अपने जनता की जिन्दगी में सुधार लाना केवल यही मेरी सरकार का मकसद है। मेरी सरकार मध्यप्रदेश की धरती पर किसी को भी गरीब नहीं रहने देना चाहती है। मेरी सरकार शासक नहीं, सेवक है। जब तक एक भी गरीब की आँख में आंसू हैं, तब तक चैन से बैठने का समय नहीं है। कोई भूखा न सोये और बिना इलाज के न रहे, हर हाँथ को काम मिले और हर एक को इज्जत की जिंदगी मिले, मेरी सरकार का यही लक्ष्य है। यह सिर्फ निरंतरता का ही जनादेश नहीं है बल्कि जनता के इस भरोसे का भी जनादेश है कि मेरी सरकार ही नए युग की आकांक्षाओं और सपनों के

साथ न्याय कर सकती है। गरीबी कम करना, आय की असमानताओं को कम करना और दीर्घकालिक रोजगार के अधिकतम अवसरों को निर्मित करना मेरी सरकार का लक्ष्य है।

04. प्रदेश की विकास प्रक्रिया को आकार देने हेतु पहले दिन से मेरी सरकार ने बिना कोई वक्त गवाए तेज गति से काम करना शुरू कर दिया है। नवीन सरकार के गठन के पहले दिन ही चार बड़े निर्णय भी लिये गए। मेरी सरकार गरीबों की खाद्य सुरक्षा के प्रति संकल्पित है। इसलिए गरीबों को गेहूँ की भाँति चावल भी एक रूपये किलो देने का निर्णय लिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को अपने खेत तक जाने के लिए सुगम रास्ते नहीं थे, अतः खेत तक उपकरण पहुँचाने और खेत में उत्पाद लाभ की सुविधा की दृष्टि से मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना भी उसी दिन प्रवर्तित की गई। उसी दिन मध्यम वर्ग आयोग का गठन करने का भी निर्णय लिया गया। भारत